



आज लोकतंत्र को सहालने वालों का तैयार करने वालों की आवश्यकता है जो इस भारत के लोकतंत्र को सही दिशा प्रदान कर सकें।

Today we need such people who can prepare defenders of democracy who in turn can give right direction to Indian democracy.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

● अंक : 67 ● वर्ष : 14 ● रायपुर, शनिवार 12 सितम्बर 2026 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रूपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

ब्रिक्स की सामूहिक ताकत को वैश्विक समाधानों में बदलना होगा : पीएम मोदी

■ सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने, और कारोबारी साझेदारियों को बढ़ाने का आह्वान किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने, स्टार्टअप को दूसरे ब्रिक्स बाजारों में विस्तार देने और कारोबारी साझेदारियों को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सामूहिक ताकत को वैश्विक समाधान में बदलने और आर्थिक विकास को नई गति देने के लिए मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर रहा है। 2006 में जब समूह की शुरुआत



हुई थी, तब इसमें चार देश थे, जबकि आज ब्रिक्स और ब्रिक्स साझेदारों को मिलाकर 21 देशों का परिवार बन चुका है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी, 40% जीडीपी और 25 प्रतिशत से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों

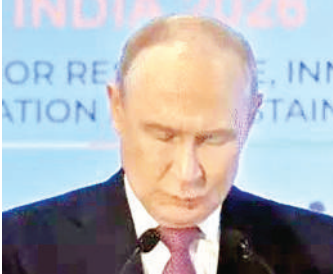
में वैश्विक जीडीपी करीब ढाई गुना बढ़ी है, जबकि ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी करीब साढ़े चार गुना हुई है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत दुनिया की तुलना में करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र भी बन रहे

हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएन्स, इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनिबिलिटी' है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापार नीति का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक अपनी सप्लाय चेन को अधिक विविध और भरोसेमंद बनाया है, जिसका परिणाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के रूप में सामने आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही शिप-बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्रांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार की जा रही हैं।

ब्रिक्स में पुतिन का अमेरिका-यूरोप पर तंज

■ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स लीडर्स ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ग्लोबल ट्रेड पर बात की



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स लीडर्स ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ग्लोबल ट्रेड पर बात की। इसमें सबसे अहम बयान पुतिन का रहा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप पर तंज कसते हुए कहा, पश्चिम अब कमजोर हो रहा है, पता नहीं ये देश खुद को 17 वरों कहे हैं। दुनिया की 40 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स देशों से आई, जी 7 की हिस्सेदारी सिर्फ 29 प्रतिशत रही।

इसके बाद पीएम मोदी ने भी बिजनेस

फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है। ये दुनिया की 40 प्रतिशत जीडीपी में हिस्सा रखते हैं। भारत व्यापार बढ़ाना चाहता है और इसके लिए सुरक्षित समुद्री रास्ते जरूरी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक, पीपीपी के आधार पर ब्रिक्स की हिस्सेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में करीब

हर पात्र परिवार को समय पर और पूरा राशन मिले, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो : सीएम साय

■ विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में राशन वितरण की नियमित निगरानी के निर्देश

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राशन वितरण में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर तत्काल कार्रवाई की जाए।



मुख्यमंत्री श्री साय ने रायगढ़ जिले को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही तक निर्धारित मात्रा में और समय पर पहुंचे, यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ राशन की उपलब्धता और वितरण की निगरानी करें।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि शिकायत से जुड़े वितरण अभिलेखों की समुचित जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार अपने हक के खाद्यान्न से वंचित न रहे। ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण और हितग्राहियों को वास्तव में दिए गए खाद्यान्न का मिलान कर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

राज्यपाल डेका ने विद्यार्थियों से किया संवाद, दिए सफलता के मंत्र



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में सैनिक स्कूल आंबिकापुर के विद्यार्थियों ने भेंट की और संवाद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए अनुशासन, आत्मनियंत्रण और कठोर परिश्रम को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी। राज्यपाल डेका ने कहा कि विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सैनिक स्कूल जैसी उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था में अध्ययन करने का अवसर मिला है। सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अनुशासन, समय की पाबंदी तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व भी सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि सफलता का आधारभूत बिंदु अनुशासन है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना किया साकार : केन्द्रीय मंत्री चौहान

■ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास हो रहे पूर्ण : केन्द्रीय मंत्री चौहान



रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के पक्के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा। सकी में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह

चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए घरों की चाबी सौंपी गई।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने

नवगठित सकी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने तथा बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा भी की। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति संबंधी पत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को सौंपा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मंत्री खुशवंत के बड़े भाई ने थामा कांग्रेस का दामन

■ भूपेश बघेल ने कराया प्रवेश, ढालदास बोले- जनता जानती है कि भाजपा क्या कर रही है



रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। भाजपा सरकार में मंत्री खुशवंत साहेब के बड़े भाई और सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु बालदास के बड़े बेटे ढाल दास ने कांग्रेस का दामन थाम ली। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा-पोरा कार्यक्रम के दौरान उन्हें कांग्रेस में प्रवेश कराया। ढाल दास ने कहा कि जनता भी जानती है कि भाजपा क्या कर रही है। अगर कांग्रेस मुझे मौका देती है तो मैं मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहूँ। पार्टी जहाँ से मुझे चुनाव लड़ने के लिए चयनित करेगी, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने से पहले मैंने अपने भाई और पिताजी से बातचीत की थी और उन्हें इस बारे में बताया था। दोनों ने अपनी सहमति दे दी। वहीं उनके भाई मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तोड़ने की नीति से काम करती है।

ढाल दास के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनका परिवार सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में एक ही परिवार के एक सदस्य के भाजपा सरकार में मंत्री होने और दूसरे के कांग्रेस में शामिल होने को सियासी तौर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। सतनामी समाज के प्रमुख धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब का परिवार बाबा गुरु घासीदास की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ है। गुरु बालदास के चार बेटे हैं- ढाल दास, सोमेश दास, खुशवंत दास और सौरभ दास। उनको एक बेटा भी है। इनमें ढाल दास सबसे बड़े बेटे हैं। गुरु परिवार का सतनामी समाज में धार्मिक और सामाजिक प्रभाव माना जाता है। गिरौधपुरी धाम और भंडारपुरी धाम से जुड़े प्रमुख आयोजनों में परिवार की सक्रिय भूमिका रहती है।

इंद्रावती भवन की लिफ्ट में 8 अधिकारी-कर्मचारी आधे घंटे फंसे

■ दम घुटने लगा, सांस लेने में परेशानी, काफी जद्दोजहद के बाद निकाला गया बाहर



रायपुर (विश्व परिवार)। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन में शुक्रवार को अचानक लिफ्ट बंद होने से 7-8 कर्मचारी और अधिकारी करीब आधे घंटे तक अंदर फंसे रहे। कर्मचारियों के मुताबिक, बंद लिफ्ट में लंबे समय तक फंसे रहने से दम घुटने जैसा महसूस होने लगा और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने के बाद वह बीच में ही अटक गई थी। अंदर फंसे कर्मचारी काफी देर तक बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। इस दौरान लिफ्ट के अंदर गर्मी और घुटन बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बाहर मौजूद कर्मचारियों ने लिफ्ट खोलने की कोशिश शुरू की। काफी जद्दोजहद के बाद दरवाजा खोला गया और सभी को बाहर निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि, इंद्रावती भवन की लिफ्ट

का लंबे समय से नियमित मेंटेनेंस नहीं हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी इस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद लिफ्ट को नियमित जांच और रखरखाव नहीं हो रहा। लिफ्ट में फंसे कर्मचारियों के मुताबिक, अगर लिफ्ट का दरवाजा कुछ और देर तक नहीं खुलता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। बंद जगह में सांस लेने में परेशानी और घुटन के कारण कर्मचारियों को खराबी महसूस हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी भवन में रोजाना इतनी बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं, इसलिए लिफ्ट का नियमित मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच जरूरी है।

नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन को ऑस्ट्रेलिया में दी गार्ड ऑफऑनर

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में गर्मजोशी और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी विरासत को दर्शाने वाली विशेष स्मोकिंग सेरेमनी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस सेरेमनी के साथ ही उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इन आस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान कैनबरा स्थित रसेल ऑफिसेज में उनका स्वागत किया गया। गौरतलब है कि स्मोकिंग सेरेमनी ऑस्ट्रेलिया की स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समारोह है। इस पारंपरिक आयोजन के जरिए अतिथि का सम्मान और स्वागत किया जाता है।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन संगठनात्मक विषयों पर गहन मंथन



■ बिलासपुर संभाग के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शिविर

रायपुर (विश्व परिवार)। संगठन सृजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा बिलासपुर संभाग के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों एवं जिला मास्टर ट्रेनर्स के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के प्रशिक्षण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावित करने तथा जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन दिया और प्रतिभागियों से इनपुट लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

पूर्व विधायक शैलेश पांडे, बिलासपुर शहर जिला अध्यक्ष सुभांशु मिश्रा, बिलासपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैट्टू ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावित करने तथा जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन दिया और प्रतिभागियों से इनपुट लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से प्रकृति संरक्षण और मातृ सम्मान का संदेश

■ केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सकी के जेटा में किया पौधरोपण

■ केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने लगाया कदम और मुख्यमंत्री श्री साय ने बादाम का पौधा



रायपुर (विश्व परिवार)। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी को बढ़ावा देने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश देते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सकी जिले के ग्राम जेटा स्थित कॉलेज ग्राउंड में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कदम का पौधा और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बादाम का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर

उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान मातृ सम्मान की भावना को प्रकृति

संरक्षण के संकल्प से जोड़ता है। अभियान के माध्यम से लोगों को अपनी माँ के सम्मान में पौधा लगाने के साथ ही उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पौधरोपण के साथ पौधों की देखभाल और उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी का भाव भी इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

यह अभियान पर्यावरण संरक्षण को केवल शासकीय प्रयास तक सीमित न रखते हुए उसे जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप देने की पहल है। अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता से हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का

संदेश अभियान के माध्यम से दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के माध्यम से देशभर में नागरिकों को पौधरोपण से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सकी जिले में केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान और मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किया गया पौधरोपण प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देता है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खूशवंत साहेब, जांगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, बिलासपुर संभागायुक्त श्री सुनील जैन, विकसित भारत जीरामजी के आयुक्त श्री तारण प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ श्री वासु जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

लगातार 4 दिन बैंक बंद, हड़ताल पर जा रहे कर्मचारी

नई दिल्ली। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक यूनियनों ने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर हड़ताल बुलाई है, जिसमें 5-डे वर्किंग सिस्टम भी शामिल हैं। आज बैंक से जुड़ी सेवाएं ठप रहेंगी। अगर आपको बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाने के लिए जाना है, तो ठहर जाइए! आज बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यूनियन ऑस्ट्रेलिया ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है, जिससे बैंक का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसके बाद शनिवार (12 सितंबर) और रविवार (13 सितंबर) को बैंक की छुट्टियां होंगी। कुछ राज्यों में लोगों को अपने बैंक से जुड़े कार्यों के लिए और भी ज्यादा दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि कई जगह गणेश चतुर्थी, मौके पर सोमवार और मंगलवार को भी बैंक बंद रहेंगे।

UFBU ने बैंकिंग सेक्टर में सुधारों से जुड़ी अपनी मांगों के तहत हड़ताल



का ऐलान किया है। उनकी एक बड़ी मांग यह है कि बैंक हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहे, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही वर्किंग हो। उनकी दूसरी मांग परफॉर्मंस-लिंकड इंसेंटिव स्कीम की समीक्षा कर विसंगतियों को दूर करना और पहले तय किए गए पेंशन सुधारों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़े प्रावधानों को तुरंत लागू करना है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जाएगी और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है।

महाराष्ट्र में ट्रक-बोलेरो भिड़े, 3 बच्चों समेत 8 की मौत



नागपुर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार को ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। पुलिस से जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 4 बजे नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर पिंपलगांव सड़क के पास हुआ। सभी लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर से नेशनल हाईवे-53 के रास्ते नागपुर जा रहे थे। ट्रक में फंसे पिकअप को निकालने के लिए दो जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का काम शुरू किया।

सर्पधां में माखवी चौहान, मधु महाप्रबंधक, श्री तरण देवान एवं वित्तसा उत्कुरी को प्रकाश, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के शानदार प्रदर्शन करके हुए क्रीडा संध (सेक्रसा) के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करके हुए आगामी राष्ट्रीय एवं अन्य उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिमान प्रकट करके सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

जला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण में आ रही बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए और निर्माण में तेजी लाई जाए। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवृत्त विकास कार्यों का लाभ नागरिकों को निर्धारित समय पर मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी।

को जान जोखिम में डालकर
उम्रता नाला पार करना पड़ रहा
है। बच्चों को कंधे पर बैठाकर
स्कूल पहुँचाने की तस्वीरें भाजपा
सरकार में इसे ही सुशासन कहते
हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि
पिछली बारिश के बाद सरकार ने
दावा किया था कि प्रदेश के जो
10,000 किलोमीटर की खराब
सड़कें हैं वह दिसंबर 2025 तक
पूर्ण कर लिया जाएगा हकीकत यह
है कि आज भी वह 10,000
किलोमीटर सड़कें खराब हैं और
बची खुची सड़कों में भी गढ़ने नजर
आ रहे हैं।

मेल ID - rmczone2@gmail.com
क्र. 35330/न.पा.नि./जोन क्र.-2/2026
रायपुर दिनांक : 11-09-2026

कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करें
श्री संतोष पाण्डेय
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (2)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. तृप्ति पाणिग्रही
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक-7
नगरपालिका विभाग रायपुर (छ.ग.)

लापरवाह हाईवा ट्रेलर का चालक धड़ाधड़ मारी स्कूटी एवं टेंपो में जबरदस्त ठोकर आँटो चालक गंभीर कॉलोनी वासियों ने किया 2 घंटा चक्का जाम

कलेक्टर को कॉलोनी की सड़क से भारी भरकम वाहनों पर रोक लगाए जाने ज्ञापन सौंपा

चार मासूम बच्चियों पर घर चलाने का आया वोड़ा पढ़ाई छूटने की प्रबल संभावना

गोपाल सिंह विद्रोही

सूरजपुर ब्यूरो दैनिक विश्व परिवार आज बिश्रामपुर बड़ागांव जान वाले कॉलोनी मार्ग पर रामनगर की ओर से आ रही है खाली हाईवे ट्रेलर ने नगर पंचायत बिश्रामपुर के समीप टेंपो एवं स्कूटी को जबरदस्त ठोकर मार दी जिससे टेंपो चालक 45 वर्षीय धर्मेन्द्र मौर्य का कमर के नीचे दोनों पर बुरी तरह से जगह-जगह क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे उन्हें गंभीर अवस्था में जिला मुख्यालय सूरजपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है वहीं आक्रोशित नगर वासियों ने भटगांव बिश्रामपुर सड़क मार्ग को 2 घंटा जाम कर दी जिससे सड़क की दोनों तरफ वाहनों कि लंबी कतारें लगी रही। सूचना मिलते ही पिलखा नायब तहसीलदार श्रीमती मीना सिंह आंदोलनकारी को समझाते हुए उन्हीं के साथ जमीन पर बैठकर आंदोलन समाप्त करने एवं अपनी माँग रखने की अपील की । आंदोलनकारी का नेतृत्व कर रहे है पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा नेता राजेश यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता आशीष यादव, भाजपा नेता इंजीनियर विनय सिंह, एल्वर मैन अक्वीनश सिंह विधायक,पार्षद अमरेश कुमार , पूर्व पार्षद जेपी यादव, भाजपा



नेता दीनानाथ सिंह यादव, पार्षद पिटू यादव आदि ने काफ़ी संख्या में कॉलोनी वासी का नेतृत्व करते हुए नायब तहसीलदार की माध्यम से कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंप कर इस मार्ग से सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी भरकम वाहनों पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाने की मांग की संबंधित ज्ञापन सौंपा तथा एक सप्ताह के अंदर पूर्णता भारी वाहनों पर रोक न लगाए जाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। नायब तहसीलदार पिलखा श्रीमती मीना सिंह ने आंदोलनकारी की मांग को सूरजपुर कलेक्टर के समक्ष रखकर समस्या निदान करने का आश्वासन दिया तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ।

कलेक्टर को प्रेषित ज्ञापन में कॉलोनी वासियों ने रखी प्रमुख मांगे- सूरजपुर कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में आंदोलनकारी ने उल्लेख किया है कि बिश्रामपुर के चोपड़ा कॉलोनी में सड़क दुर्घटना में दोनों पांव बुरी

तरह से गंवाने वाले टेंपो चालक धर्मेन्द्र मौर्य का हालत देखते हुए उन्हें आर्थिक एवं स्वास्थ्य लाभ की सभी व्यवस्था जल्द प्रदान करने तथा नगर से कोयला एवं प्लाई ऐश परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन को पूर्णतः बंद की जाए। उक्त आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आज लापरवाह ट्रेलर ने बिश्रामपुर की चोपड़ा कॉलोनी में धर्मेन्द्र मौर्य नामक टेंपो चालक को जबरदस्त ठोकर मार दी जिससे गंभीर हो गया इस दुर्घटना ने उनके दोनों पर जगह-जगह टूट गया जो अब जोड़ना मुश्किल है घर का गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है ऐसी स्थिति में उसके परिवार के समक्ष आर्थिक एवं बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था पर संकट आ गया है। पीड़ित को प्रशासन की ओर से तत्काल त्वरित सहायता राशि प्रदान करने की जाती है तो उसके बच्चों का भविष्य एवं परिवार पर प्रशासन का उपकार होगा।साथ ही बिश्रामपुर



नगरवासियों द्वारा लंबे समय से कोयला एवं प्लाई ऐश का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के नगर के अंदर से आवागमन को पूर्णतः बंद करने की मांग की जाती रही है। इन भारी वाहनों के अत्यधिक आवागमन से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है तथा आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त सड़क पर धूल, प्रदूषण एवं यातायात संबंधी समस्याओं से भी नगरवासी परेशान हैं। आज की गंभीर दुर्घटना ने इस समस्या की गंभीरता को पुनः सामने ला दिया है। नगरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोयला एवं प्लाई ऐश परिवहन करने वाले भारी वाहनों के बिश्रामपुर नगर के अंदर से आवागमन पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु तत्काल आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें। घर का मुखिया का जखमी हो जाने से परिवार का भरण पोषण पर गहरा शंकट-

उस दुर्घटना ने परिवार का भरण पोषण करने वाले मुखिया धर्मेन्द्र मौर्य अपना दोनों पर घूम चुके हैं जिनका जिला चिकित्सालय सूरजपुर में इलाज चल रहा है परिजनों ने बताया कि चोपड़ा कॉलोनी में फूलों की चार्ट का दुकान लगाकर अपना परिवार का पोषण कर रहा है दो-तीन महीना पहले टेंपो कर दी थी और इस स्कूली बच्चों को लाना ले जाना करते थे आज बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे की ट्रेलर चालक रोशन सिंह आत्मा के समारोह सिंह निवासी खर सुरा ने लगभग 12:30 बजे टेंपो चालक को बुरी तरह से ठोकर मार कर जखमी कर दी जिससे टेंपो की क्षतिग्रस्त हो गई और टेंपो चालक धर्मेन्द्र मौर्य बुरी तरह जखमी हो गए जिससे उनके चार बच्चियों का लालन पालन पढ़ाई लिखाई पर गहरा शंकट छा गया है। उनकी बच्चियों में कुमारी संध्या 20 वर्ष आरती 16 वर्ष रोशनी 13 बार सुहानी 9 वर्ष की घटना से बुरी तरह से सहमी एवं डरी हुई है।

दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मिले बस्तर सांसद महेश कश्यप, जाना स्वास्थ्य का हाल



संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और समर्पण प्रेरणादायी : महेश कश्यप

जगदलपुर (विश्व परिवार)। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव से छत्तीसगढ़ भवन में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना तथा शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। इससे पूर्व भी बस्तर संभाग के सांसदों ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना था।

उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हाल जुलाई माह में सड़क हादसे में घायल हुए थे। उनका दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में उपचार चला,जिसके बाद चिकित्सकीय सलाह पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में वे चिकित्सकों की सलाह के अनुसार छत्तीसगढ़ भवन में बेड रेस्ट पर हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित प्रदेश सरकार के मंत्री,सांसद एवं विधायक लगातार उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव स्वास्थ्य लाभ लेते हुए बेड रेस्ट पर हैं,लेकिन संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और समर्पण आज भी प्रेरणादायी है। वे स्वास्थ्य लाभ के दौरान भी संगठन की बैठकों,कार्यशालाओं और आगामी गतिविधियों को लेकर फोन कॉल एवं वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं तथा आवश्यक मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका यह समर्पण हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। हम सभी उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामाश्रय सिंह,बलदेव मंडावी,कामदेव बघेल,वनवासी मौर्य एवं सतीश बाजपेयी उपस्थित रहे।

आश्रमों की तरखीर दावों पर सवाल खड़े कर रही

भोजन से लेकर राजमर्मा की जरूरतों और रात की सुरक्षा व्यवस्था तक कई स्तरों पर अव्यवस्था

राजेश दनानी

जगदलपुर। आदिवासी विकास विभाग के आश्रमों और छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर अंदरूनी इलाकों के आश्रमों की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। लोहंडीगुड़ा और बस्तर ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित आश्रमों का जायजा लिया गया तो बच्चों के भोजन से लेकर राजमर्मा की जरूरतों और रात की सुरक्षा व्यवस्था तक कई स्तरों पर अव्यवस्था सामने आई है। आश्रमों में बच्चों के लिए सात दिनों के हिसाब से भोजन का मेनू निर्धारित है इसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है लेकिन पड़ताल में यह सवाल सामने आया कि क्या निर्धारित मेनू के अनुसार वास्तव में बच्चों को थाली तक भोजन पहुंच रहा है? ककनार,चंदेला और महिमा आश्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं और बच्चों को मिले वाली सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। यदि मेनू केवल कामजों तक सीमित रह जाए तो इसका सीधा असर उन बच्चों पर पड़ता है जिसके लिए शासन यह व्यवस्था संचालित कर रहा है। मामला सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली रोजमर्रा की जरूरती सामग्री, तेल, साबुन और टूथपेस्ट आदि को लेकर भी हर महीने कटौती के आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि बच्चों के नाम जारी होने वाली



सामग्री की वास्तविक मात्रा क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इन सामानों के वितरण और स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन कितना होता है,यह भी जांच का विषय है। आश्रमों की सबसे गंभीर तस्वीर रात की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आती है कई बालक आश्रमों

में शाम ढलने के बाद अधीक्षक की भूमिका बदल जाती है। जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी के बजाय चौकीदार और चपरासी जैसी व्यवस्थाओं के भरोसे आश्रम छोड़ दिए जाने की स्थिति बनती है। कई आश्रमों में रात के समय अधीक्षक के नदरत रहने की बात भी सामने आई है।

मोहनपुर-आमाझरिया मार्ग पर झींक नदी में पुल निर्माण का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण

झींक नदी पर 120 मीटर लंबे पुल निर्माण के लिए 69 लाख रुपए का प्रावधान वर्षा ऋतु के पश्चात झींक नदी पर पुल निर्माण के लिए बोरिंग कार्य होगा शुरू

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- जिला सूरजपुर के मोहनपुर भोटेकलापारा से आमाझरिया मार्ग पर झींक नदी पर पुल नहीं होने के संबंध में कार्यपालन अभियंता ने जानकारी दी है कि झींक नदी पर पुल निर्माण कार्य लम्बाई 120.00 मी. कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट में मांग संख्या 42/5054 (4149) योजना अन्तर्गत पुलो का निर्माण कार्य बजट मद क्र. 5658 अन्तर्गत 69.00 लाख रुपए की राशि प्रावधान के साथ सम्मिलित है। उक्त कार्य का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्षाऋतु पश्चात बोरिंग कार्य पूर्ण कराकर जी.ए.डी. एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर उच्च कार्यालय से अनुमोदन कराकर प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाएगा। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य की निविदा कर कार्य प्रारभ किया जा सकेगा।

जलस्तर बढ़ हुआ है। बताया जा रहा है कि सिकासार और सोदूर जलाशय से पैरी नदी में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव काफी तेज है। इसी तेज धार के बीच युवक एनीकट पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक पानी की चपेट में आने से वह बह गया।

युवक की पहचान अब तक नहीं- हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस एवं प्रशासन की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी है। फ्लिहाल बहने वाले युवक की पहचान नहीं हो सकी है। तेज बहाव और बढ़े जलस्तर के चलते रेस्क्यू टीम को तलाश अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया। टीम शनिवार को दोबारा तलाश अभियान शुरू करेगी। सिकासार और सोदूर जलाशय से छोड़ा गया पानी- लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में नदी-नालों का



नदी में कोपरा से चौबेबंदा तक करीब 14 किलोमीटर क्षेत्र में सघन तलाश अभियान चलाया। पाण्डुका के साथ मारगलोट पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नदी के अलग-अलग हिस्सों में युवक की खोज की गई। हालांकि देर शाम तक

बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के कारण वे सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलते ही पाण्डुका पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। कोपरा से चौबेबंदा तक 14 किलोमीटर तलाश- रेस्क्यू टीम ने पैरी



का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते वह नदी की धार में ओझल हो गया। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। युवक के बहने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी के

संक्षिप्त समाचार

अंधे मोड़ पर सुरक्षा की दरकार, सड़क किनारे पेड़ की कटाई और दोनों ओर स्पीड ब्रेकर की मांग



जगदलपुर। गणपति के आगे गुरयाभार नाला के पास सड़क पर बना अंधा मोड़ राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने इस स्थान पर सड़क किनारे मौजूद पेड़ की आवश्यकतानुसार कटाई करवाने तथा मोड़ के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अंधे मोड़ के कारण सामने से आने वाले वाहन आसानी से दिखाई नहीं देते। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात के समय स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग एवं प्रशासन से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कर सड़क किनारे बाधक पेड़ की कटाई, दोनों ओर स्पीड ब्रेकर तथा आवश्यक चेतावनी संकेतक लगाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।

चाकू लहराकर युवक को दी जान से मारने की धमकी, बस्तर पुलिस ने आरोपी को दबोचा



जगदलपुर। शहर के कुम्हारपारा इलाके में नशा करने से मना करने पर एक युवक द्वारा चाकू लहराकर धमकाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद बोधघाट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, कुम्हारपारा निवासी कुर्सो सोना ने थाना बोधघाट में शिकायत दर्ज कराई कि 10 सितंबर की सुबह उसके आँटो के पीछे रोनिन बघेल उर्फ खरगोश नशा कर रहा था। उसे नशा करने से मना करने पर आरोपी कथित रूप से गाली-गलौज करने लगा और बांस के डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाई। आरोप है कि इसके बाद युवक ने अपने पास रखा धारदार चाकू निकालकर लहराया और जान से मारने की धमकी देते हुए शिकायतकर्ता को डराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोधघाट पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी रोनिन बघेल उर्फ खरगोश (20 वर्ष), निवासी कुम्हारपारा, गुरु घासीदास वाई, जगदलपुर को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसके कब्जे से धारदार चाकू जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनन्दन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार दत्ता भोत्रे के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी रामेश्वर चौहान के नेतृत्व में की गई।

माय भारत युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

बिलासपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माय भारत) बिलासपुर द्वारा क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, सरकंडा में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के समापन समारोह में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए युवाओं की ऊर्जा एवं क्षमता का सकारात्मक दिशा में उपयोग कर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण में बिलासपुर, मुंगेली, गौरिला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, कोरिया एवं एमसीबी जिले के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास, टीम भावना, सकारात्मक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका की भावना विकसित करना रहा।

दैनिक विश्व परिवार



संपादकीय

मीडिया कवरेज का अनुरोध

मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते, यह जग-जाहिर है। इसलिए भारत का प्रेस कांफ्रेंस ना रखने का अनुरोध-असामान्य नहीं है। असामान्य अमेरिका का उस अनुरोध के प्रति दिखाई गई बेकद्री है। क्यूटीनकित स्तर पर हुए संदेशों के आदान-प्रदान की सार्वजनिक चर्चा कर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि ट्रंप काल में अमेरिका के मन में भारतीयों नेतृत्व के प्रति कितनी बेकद्री भरी हुई है। जो उन्होंने बताया, उससे यह और भी स्पष्ट हुआ। यह सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर यह स्थिति उसने क्यों बनने दी है? भारत में अमेरिकी राजदूत गोर ने एक कार्यक्रम में बताया कि जून में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने का कार्यक्रम बना, तो भारतीयों विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन सवाल-जवाब वाली पूरी कांफ्रेंस ना रखी जाए। गोर ने यह नहीं कहा, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की इस शर्त पर अमेरिका सहमत हुआ। लेकिन मुलाकात के बाद मोदी और डॉनल्ड ट्रंप मौफीडिया के सामने आए, तो शुरुआती बयान पूरा होते ही ट्रंप ने वहां मौजूद पत्रकारों से खुद ही पूछ लिया कि क्या कोई सवाल है? उसके बाद वे 45 मिनट तक सवालों के जवाब देते रहे, जबकि मोदी खामोशी बैठे रहे। इस खुलासे से बनी अदहज स्थिति के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि किसी शीर्ष नेता के विदेशी दौरों से पहले मीडिया में उनकी उपस्थिति के प्रारूप को लेकर संबंधित देशों के बीच चर्चा होना 'मानक प्रोटोकॉल' है। भारतीय पक्ष ने अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ही मीडिया कवरेज का अनुरोध किया। मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते, यह जग-जाहिर है। इसलिए भारत की तरफ से ऐसा अनुरोध असामान्य नहीं है। असामान्य अमेरिका का उस अनुरोध के प्रति दिखाई गई बेकद्री है। अपेक्षित था कि ट्रंप के उस व्यवहार पर भारत सरकार तुरंत सार्वजनिक विरोध जताती। मगर ऐसा नहीं किया गया। अब धेरूल् जनमत की संभालने के लिए 'सरकारी सूत्रों' से ब्रीफिंग कराई गई है कि मीडिया के सामने विदेशी नेताओं के साथ ट्रंप के 'अप्रत्याक्षित व्यवहार' के कारण उपरोक्त अनुरोध किया गया। इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन असल मुद्दा उस अनुरोध के प्रति का ट्रंप का रहा व्यवहार है।

आलेख

सो, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं

हरिशंकर व्यास

आनंद फिल्मों में हीरो का एक लाजवाब वाक्य है, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और मेरे हिसाब से भारत के परमाणुमंत्रियों को परखने का भी यह एक सत्य-तत्व है। लालबहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल लंबा नहीं हुआ मगर बड़ा था। शास्त्री ने 1965 के युद्ध की चुनौती में ठोस लीडरशिप से वह कमाल किया, जिसने देश के मनीषल को ऊंचाई दी नरसिंह राव मौनी थे, पर पंजाब, कश्मीर, उत्तर-पूर्व में अलगाववाद और अंतःकावद की कम्मर दृढ़ता से तोड़ी तो आर्थिक सुधारों और कूटनीति से वह दिशा बनाई, जिससे हिंदू विकास दर की जड़ता खत्म हुई। ऐसे ही वाजपेयी हों या डॉ. मनमोहन सिंह, इन्होंने देश और पूरे समाज को साथ लेकर चलने को कोशिश की। अमेरिका से परमाणु करार कर भारत तककों पुराना परमाणु अखूतपन खत्म किया। भारत दुनिया की तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। पर इनमें से एक भी प्रधानमंत्री ने (या नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी आदि किसी ने भी) अपनी सत्ता के पांच, दस, पंद्रह साल होने का तमाशा नहीं बनाया। अपना कीर्तन नहीं करवाया। सत्ता को नौटंकी नहीं बनाई। देश को विश्व राजनीति में लुढ़कता लोटा नहीं बनाया, बल्कि अपनी बुद्धि, वाणी और गरिमा से भारत की पहचान बनवाई। जबकि नरेंद्र मोदी के लंबे पच्चीस साला पावर में क्या ऐसा एक भी बड़ा काम है? क्या उनके कार्यकाल से भारत की संस्थागत क्षमता, उत्पादकता या सामाजिक शक्ति की श्रैवृद्धि हुई या उलटें बनावदी हुई? बतौर मुख्यमंत्री उनका गुजरात मोदी हों या बतौर प्रधानमंत्री 'अच्छे दिने', अमृतकाल, विकासपरत भारत जैसे सैकड़ों जुमले, किसी भी एक की असलियत, गहराई और परिणामों को यदि जांचें तो अल्टीमेटली वही सत्य उभरेगा, जिनसे उनका कार्यकाल सुधीर्जन से निर्र्द्ध हुआ है। हां, लालकृष्ण आडवाणी ने अप्रैल 2014 में कहा था मैं चिन्ते हूँ कि अपना चेला नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उनसे अधिक प्रतिभाशाली और कुशल इवेंट मैनेजर कभी नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी ने चार अप्रैल 2002 को अहमदाबाद में मोदी को राजभवन याद कराते हुए कहा था, 'राजा और शासक के लिए प्रजा-प्रजा में देव नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संसदाध्यक्ष के आधार पर'। एक और उदाहरण 'इंडिया टुडे' पत्रिका की गुजरात चुनाव जीतने के बाद की यह कवर स्टोरी है, 'मास्टर ड्रिवाइडर' (6 जनवरी 2003)। फिर मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभाली तो अरुण शोरी का यह अविस्मरणीय कथन सुनाई दिया कि सरकार आर्थिकी नहीं चला रही है, बल्कि वह हेडलाइंस का प्रबंधन कर रही है। फिर नोटबंदी हुई तब अरुण शोरी ने उसे अब तक की सबसे बड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग स्क्रीम और बेवकूफीपूर्ण भार झटका कहा था। चार अलग समय, अलग संदर्भ और अलग-अलग वर्णन, राजधर्म, मास्टर ड्रिवाइडर, इवेंट मैनेजर और हेडलाइन मैनेजरजैत पच्चीस साल बाद इनमें से कौन-सा वर्णन अप्रासंगिक हुआ? पूरे पच्चीस वर्षों की यही पहचान है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी थकते नहीं हैं। उनको शो, तमाशा कभी ठिठकता या रुकता नहीं। और भी क्योंकि नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी हूं तो इस मजेदार रियलिटी को भी जानें। गुजरात के सीएमओ का प्रशासन जब पीके मिश्रा, कैलाशनाथन, एपीएम जैसे अफसर संभालते थे, तब भी नरेंद्र मोदी जनसंपर्क अधिकारी जगदीश ठक्कर के साथ बैठकर प्रेस रिलीज बनवाते थे और 'गुजरात समाचार', 'संदेश' आदि में हेडलाइन प्रबंधन स्वयं संभालते थे। दिल्ली आए तो जगदीश ठक्कर को भी साथ ले कर आए। तब उनको प्राथमिकता समाचार पत्र थे। फिर टीवी हुआ। ठक्कर की मृत्यु के बाद मोदी ने हीरेन जोशी को आगे किया। राष्ट्रीय मीडिया को मोदी दुकान बनाया। अखबार, टीवी चैनलों की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई तो रीशल मीडिया का प्रबंधन शुरू हुआ। और अब वक्त इंस्टाग्राम का है तो सोशल बना कर अपना मुखंड युवाओं के गले उतार रहे हैं। मंच बरला, माध्यम बरला पर मोदी की मूल राजनीति और शासन की कला याकि हेडलाइन और नैरेटिव पर नियंत्रण को तनिक भी नहीं भूला। लगता है अब पच्चीस साला मोदी मॉडल आउटडेटेड हो रहा है। सब मैनेज हो गया है। मगर रील्स देखते, मीम बनाते, सवाल पूछते और सत्ता का मजाक उड़ाते नए युवाओं का क्या करें?

विचार-पक्ष

रायपुर, शनिवार 12 सितंबर 2026

भूमिगत संरचना का मानचित्रण: संपूर्ण प्रणाली और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के ज़रिए किस प्रकार आईसीएआर की 'मृदा आसूचना' भारत के विशाल अवसंरचना विस्तार को नया रूप दे रही है

एम.एल. जाट और एन.जी. पाटिल



भारत अतूतपूर्व और ऐतिहासिक गति से अपने डिजिटल, फिज़िकल (भौतिक) और मिज़ेडल (फिज़िकल+डिजिटल) भविष्य का निर्माण कर रहा है। देश हर वर्ष औसतन 4.5 लाख से अधिक रकम किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जबकि साथ ही लगभग 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और 6,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा रहा है और हर वर्ष लगभग 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जा रहे हैं। इस व्यापक विस्तार का अर्थ है कि देशभर में डिजिटल कनेक्टिविटी के 22.8 लाख किलोमीटर के आश्रयजनक विस्तार वाले बहुतरासी रातीय विस्तार के साथ-साथ, देश प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर राजमार्ग और 12 से 15 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण कर रहा है। फिर भी, जैसे-जैसे ये विस्तृत परिवहन गलियारे, अल्ट्रा-मेगा साँठों और विशाल डिजिटल नेटवर्क विकसित पा रहे हैं, पृथ्वी विज्ञान के नेतृत्व में एक शांत तकनीकी सहयोग भूमिगत की सतह के ठोका नीचे हो रहा है। बड़े परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों को अक्सर पहले से मिट्टी की खुदाई की लागत का अनुमान तैयार करना पड़ता है, भले ही पहले से कोई भूवैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध न हो। चूंकि परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया की समय-सीमा बहुत कम होती है, इसलिए त्वरित और विद्वत्सन्नि मृदा संबंधी आंकड़े जिस जोजिम को काफी महत्व तक काम कर सकते हैं—विशेषकर तब, जब परियोजना भारत के बाहर स्थित हो और स्थानीय भाग संबंधी आंकड़ों तक पहुंच कठिन हो। इसके अलावा, बोली जीतने के बाद, परियोजना क्रियान्वयन-कर्ताओं को बार-बार आने वाली करोड़ों रुपये की समस्या का सामना करना पड़ता है: नम मिट्टी में आसानी से खुदाई करते हुए इंजीनियरिंग दल अचानक भूमिगत चट्टान की कठोर दीवार से टकरा जाता है, या ग्रामक की कपास मिट्टी पर बनाई इमारतें सड़क में दूरारे पड़ने लगती हैं और वह उखड़ने लगती हैं। काम रुक जाता है, मशीनों बेकार खड़ी रहती हैं और परियोजना की लागत असमान बढ़ने लगती हैं। इस महत्वपूर्ण सूचना अंतराल को पाटने के लिए, नागपुर स्थित आईसीएआइएड्यूकेशन मृदा संबंधी एवं भूउपयोग स्थिति आँसोएसआइएएस एवं

एलएचपी) के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी प्रतिमान विकसित किया है: मुदा आसूचना-आधारित पूर्वानुमानात्मक इंजीनियरिंग। दशकों से उपलब्ध विविध विज्ञान संबंधी आंकड़ों को उन्नत मशीन लर्निंग के साथ जोड़कर, आईसीएआर बुनियादी ढांचा योजनाकारों को जमीन में पहली फसलें लगाने से पहले ही पृथ्वी के बारे में एक्स-रे दृष्टि प्रदान कर रहा है—यह सिद्ध करते हुए कि कृषि अनुसंधान खेतों से कहीं आगे राष्ट्रीय विकास का एक आधारभूत चालक है।

गति और विस्तार की
अनदेखी की गई चुनौतियां

भारत में वर्तमान अवसरचंचना विस्तार की अत्यधिक तीव्र गति के कारण पारंपरिक नियोजन स्वयंयं एक बाधा बन गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल डिजिटल फुटप्रिंट लगभग 19.35 लाख करोड़ रू. किलोमीटर से बढ़कर 42.36 लाख रू. किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो कई वर्षों में हुए वार्षिक विस्तार को दर्शाता है। इसी हालिया वृद्धि वार्षिक अवधि में, देश ने 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इसी दौरान, भारतीय रेलवे ने 33,000 से अधिक रू. किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, जो औसतन लगभग 6,600 रू. किलोमीटर प्रतिवर्ष है और ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को लगभग 99.66 तक पहुंचाता है, जिसकी दर प्रतिदिन 15 से अधिक रू. किलोमीटर की अनुमति प्रदान करता है। स्वच्छ ऊर्जा में, भारत ने अपनी प्रमुख सौर योजना के तहत 54 से 56 बड़े पैमाने के सौर पार्कों को मंजूरी दी है, जिनकी स्वीकृत क्षमता लगभग 39.5 गीगावाट है, जिससे 100 से अधिक सार्वजनिक और निजी पार्कों में कुल ग्राउंड-माउंटेड सौर क्षमता 122 गीगावाट से अधिक हो पाई है। इन विशाल कार्यों में शामिल कई सरकारी और निजी एजीएनसीयाँ-चाहे वे भूमिगत संचार लाइनों को बिछाने, सिंचना परियोजनाएं खड़े करने या विशाल सौर परियोजनाओं को आधार प्रदान करने का काम कर रही हैं-सटीक भूमिगत आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं। फिर भी, पारंपरिक प्राथमिक भू-तकनीकी सर्वेक्षणों के काफी समय और लागत लागू हैं। चूँकि, परियोजनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, कि महत्वपूर्ण मुद्दा जांच अक्सर छोड़ दी जाती हैं या सीमित कर दी जाती हैं। इसका परिणाम? अनिश्चित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), भ्रामक लागत अनुमान और बोलीदाताओं के लिए गंभीर वित्तीय जोखिम।

कृषि-अवसंरचना संबंध

आईसीएआर-एनबीएसएस एवं एल्यूमी ने इस सूचना-अंतराल को एक प्रमाणित, समय-परिचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूर किया है, जो पूरे भारत और कई अन्य देशों में काम करती है। उपग्रह रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन लॉजिस्टिक्स का उपयोग करके, आईसीएआर स्थल-विशिष्ट भू-तकनीकी मुदा गुणों, जैसे मृदा की गहराई, अंतिम वहन क्षमता (सिविल इंजीनियरिंग संरचना को सहारा देने में निर्णायक

कारक), स्थूल घन्तल आदि का पूर्वानुमान लगाता है, जिसके लिए भूमि की धीमी, महींगी और विघटनकारी इंड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं होती। यह पद्धति पूरी तरह से स्वचालित पायपलाइन के अंतर्गत बहु-स्तरीय भू-स्थानिक इनपुट पर मशीन-लर्निंग रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करता है। उपग्रह चित्रों, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, भू-भाग की ढलान संबंधी व्युत्पन्न आंकड़ों, स्थल-विशिष्ट पूर्वानुमान तैयार करता है। यह प्रणाली मृदा की स्थितियों/लॉजी और भूजल स्तर को संसाधित करके, आईसीएसएआर का मुद्रा वर्गीकरण इंजन सटीक, स्थल-विशिष्ट पूर्वानुमान तैयार करता है। यह प्रणाली मृदा की गहराई (नम, कठोर या मिश्रित परतों का लगातार अनुमान) और मापदंडों का सटीक पूर्वानुमान लगाती है। इन मापदंडों का उपयोग इंजीनियरिंग एजेंसियों द्वारा प्राथमिक भू-तकनीकी डिजाइन, विस्तृत परीोजना प्रारंभ (डीपीआर) तैयार करने और बोली-पूर्व लागत अनुमानों के लिए सौंपी किया जाता है। परंपरिक क्षेत्र सर्वेक्षणों की तुलना में, यह डिजिटल समाधान लागत और समय दोनों में 75% की कमी करता है। तीन सदस्यों की एक छोटी टीम प्रतिदिन लगभग 1,000 किलोमीटर लंबे मार्ग को संसाधित कर सकती है। जिससे यह बड़े पैमाने पर, समयबद्ध राष्ट्रीय नियोजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बन जाता है। भारतभर में 50,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इस पूर्वानुमानात्मक टूटिकोणी का सत्यापन करने के बाद, क्षेत्रों में सत्यापित आंकड़ों के मुकाबले लगभग 80% क्षेत्रों को पूर्वानुमान सटीकता (अर्ध मान लगातार 0.78 से अधिक) प्राप्त हुई है, यहां तक कि कम आंकड़ों वाले क्षेत्रों में भी। अब इन परिकलन विधियों (एल्योरिदम) को मानकीकृत कर दिया गया है।

वैश्वेक उपस्थिति और
वाणिज्यिक विश्वसनीयता

इस प्रणाली का भारत के अत्यंत विविध भौगोलिक क्षेत्रों में कठोर क्षेत्र-परीक्षण किया गया है—उत्तराखंड और असम के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तथा दक्षिण के पठार और सिंधु-गंगा के मैदानों तक। क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर मानकीकृत की गई यह प्रौद्योगिकी अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है। प्रमुख सार्वजनिक और निजी अवसरचना कंपनियों भारत और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में 2,00,000 से अधिक रूट-किलोमीटर का मानचित्रण करने के लिए इस प्रणाली को अपना चुकी है, जिससे आईसीएआर के अनुसंधान परिातित के लिए संसाधन जुटाने के साथ-साथ यह बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत भी हो रही है और भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने तथा वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा रहा है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, स्टरलाइट इंटरनेशनल लिमिटेड, टाटा प्रोजेन्सस लिमिटेड और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड सहित प्रमुख वैश्विक अवसरचना कंपनियों ने इस समाधान को अपनाया है। केईसी इंटरनेशनल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जो 100 से अधिक देशों में परंपरेण लाइनों के डिजाइन और वित्तिका निर्माण करती है, के लिए मुद्रा संबंधी आंकड़ों वित्तीय अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निचले संबंधी गतिविधियाँ और परियोजना जाँचिम पूरी तरह से मुद्रा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ऐसे उद्योगों में, जहाँ 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का आधार पर मार्जिन में मामूली 0.1% की कमी भी 6 करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान में बदल जाती है, इसी तरह मुद्रा आसुचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात, सूऊदी अरब, नाइजर, रूस, केन्या, मंगोलिया, मोल्दोवा, मैक्सिको, मलेशिया, अबू धाबी, नेपाल, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया जैसे भौगोलिक रूप से जटिल देशों में पारेषण लाइन परियोजनाओं के लिए बोली लगाते समय, मुद्रा संबंधी आंकड़ों की एकमात्र या वास्तवसचि स्थिति का निष्पक्ष/सही प्रतिनिधित्व न करने वाले आंकड़े लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। आईसीएआर की प्रौद्योगिकी विश्वस्तरीय तृतीय-पक्ष सत्यापन प्रदान करती है, जो व्यापारकों या परियोजना प्रबंधकों द्वारा मुद्रा की स्थिति के संबंध में किए गए दावों की जांच के लिए एक निष्पक्ष सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करती है, जिससे बोली लगाने में विश्वास बढ़ता है। छोटी-मालापर वसी निविदाओं के मामले में, जहाँ समय या निर्वाही सीमाओं के कारण भौतिक सर्वेक्षण संभव नहीं होते, यह पूर्वानुमानात्मक आंकड़ा इस कमी को पूरा करता है।

राष्ट्रीय प्रगति की प्रेरक

इस आंकड़े और विश्लेषण की सफलता ने अन्तरसंरचना क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को आईसीएआर की प्रौद्योगिकी को विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों में व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे इसकी उपयोगिता विद्युत पारेषण लाइनों से आगे बढ़कर रेलवे, सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों और भूमातृ-अभिलेख तक विस्तृत हो गई है। उन्नत मृदा विज्ञान और उपयोग करने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों के जोषिख को कम करने हुए, कृषि अनुसंधान ने स्वयं को भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि के एक अपरिहार्य चालक के रूप में सिद्ध कर दिया है। यह प्रौद्योगिकी दर्शाती है कि मृदा विज्ञान में निवेश केवल देश का पेट नहीं भरता, बल्कि उसके वैश्विक भविष्य का आधारशिला भी तैयार करता है। इस सफलता के आधार पर, आईसीएआर के वैज्ञानिक अब 90 मीटर रिजॉल्यूशन वाले मृदा गहराई मानचित्र और हाल ही में पूर्वी रिजॉल्यूशन वाले मृदा बनाबत मानचित्र जैसे नए सूत्रीय मानचित्र डिजिटल मृदा मानचित्र का आत्मविश्वास के साथ तैयार कर रहे हैं। ये मानचित्र निम्न भविष्य में भारत की डिजिटल कृषि की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, विशेष रूप से भारत के किसानों को भूखंड-विशेष समाधान उपलब्ध कराते

(लेखक एम.एल. जाट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक हैं, एन.जी. पाटिल आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी), नागपुर के निदेशक हैं)

अर्थव्यवस्था में सेवा निर्यात की अहमियत

डा. जयंतीलाल भंडारी

नवाचार और लक्षित नीतियों के संतुलन से भारत को वैश्विक सेवा निर्यात के अहम केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना होगा। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना होगा कि देश में महज 8.25 प्रतिशत व्युत्पन्न ही रोजगारपरक कौशल के आधार पर डिग्रियों के अनुसूच रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं इन दिनों सेवा निर्यात पर प्रकाशित हो रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने वैश्विक सेवा निर्यात को भारत की आर्थिक ताकत के रूप में रेखांकित किया जा रहा है। दुनिया में भारत को श्रेष्ठ सेवा निर्यात प्रदाता देश के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। कहां जा रहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के प्रति अचूक जागरूकता के बीच यह सेवा निर्यात भारत के कुल निर्यात को नई ऊंचाई दे रहा है, वहीं यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता हुआ भी दिख रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के तहत अप्रैल-जुलाई 2026 के चार महीनों में कुल सेवा निर्यात 6.38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 142.64 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। ऐसे में उम्मीदी की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में सेवा निर्यात पिछले वित्त वर्ष के 421.32 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से भी ऊपर पहुंच जाएगा। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्टों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ही भारत के सेवा निर्यात ने वैश्विक सुस्ती के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। इस अवधि के दौरान पेशावर परामर्श, सेवा निर्यात सेवाओं और डिजिटल समाधानों के अंतरराष्ट्रीय मांग में लगातार उछाल दर्ज किया गया। भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों के विस्तार और विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय सेवा निर्यात प्रदाताओं को विश्वी बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान की है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष के दौरान भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और सांफ्टवेयर सेवा निर्यात में व्यापक विस्तार हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल परिवर्तन की बढ़ती मांग ने इस निर्यात को नई दिशा दी है। सांफ्टवेयर उत्पादों के साथ-साथ थियरिंग, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं ने निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित अनुकूल कर राहतों और नीतिगत सुधारों से भारतीय कंपनियों को वैश्विक ग्राहकों को



आकर्षित करने में सीधी मदद मिली है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपने पारंपरिक बाजारों के अलावा नए भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक वितरण का विस्तार किया है। विश्व व्यापार संगठन का कहना है कि वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले दो दशकों में दोगुनी से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वैश्विक क्षमता कटौत और डिजिटल समाधानों की वैश्विक मांग ने भारत को विश्व के शीर्ष सेवा निर्यातक देशों में मजबूती से स्थापित कर दिया है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत ने दुनिया में 7वां स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि वर्ष 2001 में भारत 24वें स्थान पर था। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि हाल ही के महीनों में अमरीका द्वारा कठोर वीजा नियमों, वीजा साक्षत्कार पर अस्थायी रोक और वीजा शुल्क में वृद्धि जैसे सेवा निर्यात की राह में कठोर कदमों के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से जुलाई की अवधि में भारत से सेवा निर्यात अमरीका को भी बढ़ावा मिला है। यदि हम भारत से अमरीका को सेवा निर्यात में वृद्धि के मुख्य कारणों को देखें, तो पाते हैं कि अमरीका की वीजा पार्यवर्ती (जैसे एच-1बी वीजा फ़ैस) में अत्यधिक वृद्धि के कारण अमरीकी कंपनियों ने भारत-अमरीका में वैश्व क्षमता कटौत का विस्तार किया है। इससे भारत में रहते हुए भी काम का रखाना बढ़ा है। टीसीएस, एडोबे, मैसैरस और विप्रो जैसे भारतीय गिगन आउट कंपनियों ने अमरीका में स्थानीय नवासियों की भर्ती

बहुत है, जिससे नए बीजा प्रयोजन पर निर्भरता कम हो गई है। कृषि बुद्धिमता, कलाउड कंप्यूटिंग और रिमोट सेंसिंग को मॉडल की बढ़ती मांग ने बीजा यात्रा की आवश्यकता को घटाकर डिजिटल सेवा प्रदायकों को अनपेक्षित रूप से बल दिया है। निःसंदेह भारत मुक्त व्यापार समझौते (एमपी) के माध्यम से सेवा निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी कोई दो बातें नहीं हैं कि भारत के वैश्व क्षमता केंद्रों (जीसीडी) से। एमपी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इससेवा निर्यात के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इस समय भारत 217 वैश्व क्षमता केंद्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर आगे बढ़ रहा है। दुनिया के करीब 55 प्रतिशत से अधिक वैश्व क्षमता केंद्र अकेले भारत में हैं। भारत में ये केंद्र सीधे तौर पर 23 लाख से अधिक पेशेवरों को रोजगार दे रहे हैं और यह क्षेत्र सालाना लगभग 100 करोड़ डॉलर का राजस्व पैदा कर रहा है। भारत में वैश्व क्षमता केंद्रों की रफ़्तार में तेजी की स्थिति यह है कि दो साल पहले (साल 2024 में) जहां भारत में एक हजार से अधिक नया केंद्र खुल रहा था, वहीं बाजार में बहुत प्रतिक्रिया 1 नए केंद्र की स्थापना के रूप में बदल चुकी है। निःसंदेह सेवा निर्यात की इन विभिन्न अनुकूलताओं के बावजूद भारत से सेवा निर्यात को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए कई ढांचगत और नीतिगत चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है। हाल ही में नीतिविशेषज्ञों ने 'भारत का सेवा क्षेत्र : पेयवेब सेवाओं में नियामक

है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सेवा क्षेत्र में मौजूद निर्यातनियामक बाधाओं को समाप्त कर भारतीय पेशेवरों की वैश्विक स्पर्धाक्षमता को बढ़ावा देने का मबूत करना है। रिपोर्ट के तहत सेवा क्षेत्र में निर्यातनियमित को तेजी से बढ़ावा की राह में जो चुनौतियाँ बाधाएँ सामने आई हैं, उनमें कानूनी, लेखा, वास्तुकला और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निर्यातनियामक बाधाओं का समाप्त करना प्रमुख बाधाएँ हैं, जिससे निर्यातनियमित से जुड़े पेशेवरों की वैश्विक गतिशीलता प्रभावित होती है। जो चुनौतियाँ से निपटने के लिए जो नई रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सामान्यकरण के माध्यम से उपरते खण्डों को अपनाना, सेवा मूल्य-वैधता में सुधार करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं व मानकों को लागू करना, निर्यातनियमित के निरंतर विकास हुए सतत प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, निर्यातनियमित योग्यताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए अन्य देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौतों को बढ़ावा देना और कारोबार सुगमता में सुधार करना शामिल हैं। निर्यातनियमित अलावा देश से सेवा निर्यात को ऊँचाई देने के लिए आईएन और बातों पर ध्यान देना होगा। आईटी के अतिरिक्त अंतरिक्ष, औद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और चिकित्सा पर्यटन जैसे क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा दिया जाना होगा। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यक्षम को उपरत करने की नई तकनीकों में तेजी से दक्ष बनाने के प्रयास किए जाने होंगे। नए अंतराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में भारतीय पेशेवरों की सुगम आवाजियों के प्राधान्य पर विशेष जोर दिया जाना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम सेवा निर्यातकों को वित्तिय सहायता देकर अंतराष्ट्रीय बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ाई जानी होगी। नवाचार और लक्षित नीतियों के माध्यम से भारत को वैश्विक सेवा निर्यात के अहम केंद्र के रूप में स्थापित किया जाना होगा। इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि देश में महड 8.25 प्रतिशत युवक ही रोजगारपरक कौशल के आधार पर डिग्रियों के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में स्कूल-कॉलेजों में पढाई के साथ नई पीढ़ी को रोजगारपरक कौशल से सुसज्जित करना होगा। ऐसी रोजगार कौशल से सुसज्जित नई पीढ़ी सेवा निर्यात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। उम्मीद करे कि पश्चिम एशियाई संकट तथा मधेनजर गेम चेंजर भूमिका निभाएगी। ऐसे में देश से निर्यात की राह पर रस्ता से बढते हुए वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के सेवा निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगा। साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलते हुए दिखाई देगी।

